

विचार बिन्दु

आनंद वह खुशी है जिसके भोगने पर पछताना नहीं पड़ता। -सुकुवत

सरकार काम कर रही है यह बताने के लिये ग्राम रथ

सरकारें जब काम करती हैं तो उन्हें अपना काम आम जनता को दिखाना भी होता है ताकि सत्तारूढ़ दल के सदस्य जब फिर वोट मांगने अवाग के बीच जायें तो उन पर यह तोहमत न लगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार के कामों का भयंकर प्रचार भी चुनावों में किसी काम नहीं आया था। हमने राजस्थान में भी विधानसभा के पिछले चुनावों में धुआंधार प्रचार के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर होते देखा है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब सरकार के पूरे कार्यकाल में प्रचार अभियान सतत चलाया जाने लगा है। एक के बाद एक सरकारी इवेंट किये जाने लगे हैं, जिससे उसके वे काम जनता को दिखें जिसे वह बताना चाहती है। ऐसा ही एक इवेंट 'ग्राम रथ' का राजस्थान में चल रहा है। सरकारों विकास कार्य करती हैं, योजनाएं बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं, परंतु यह सब तब तक राजनीतिक रूप से सार्थक नहीं होता जब तक वह आम जनता की चेतना में न दिखने लगे। इसके लिये पेशेवर प्रचार विशेषज्ञ नये-नये तरीके ईजाद करते रहते हैं। उनका नया आइडिया यह है कि प्रचार चुनावों के समय ही नसी प्रसारित चलाया जाए। प्रचार के माध्यम से ग्राम रथ का प्रचार राजकोष से हो जाता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि सरकारों का प्रचार पर खर्च साल-दर-साल बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में हम राजस्थान सरकार के वर्तमान में चल रहे 'प्रचार रथों' के अभियान को समझ सकते हैं। राजस्थान सरकार के प्रचार का यह केवल साधारण सूचना अभियान नहीं है, बल्कि ऐसे अभियान आधुनिक राजनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभर रहे हैं। इन्हें केवल प्रचार का माध्यम मानना एक सीमित दृष्टिकोण होगा। इनके पीछे कई परतों वाली रणनीति कार्य करती है कि शासन लोगों को दिखे, जिसका लाभ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिले। इसलिए इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के पदाधिकारी इन रथों के सारथी बनाये गए हैं।

डिजिटल युग में भी भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां प्रत्यक्ष संपर्क का महत्व बना हुआ है। प्रचार रथ इस प्रत्यक्ष संपर्क का माध्यम बनते हैं। इसलिए राजस्थान की 200 में से 183 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे रथ चल रहे हैं। ये सभी ग्राम ग्रामीण हैं। शेष 17 विधानसभा क्षेत्र शहरी हैं। जहां इनकी जरूरत नहीं समझी गई है। शायद ऐसा माना गया है कि जहां स्मार्टफोन पर सीधे या इनप्लूएंसरों के जरिए प्रचार पहुंचा दिया जाएगा। सरकारी योजनाएं अक्सर जटिल होती हैं और उनकी जानकारी हर नागरिक तक स्वतः नहीं पहुंचती। कई बार लाभार्थी स्वयं यह नहीं जान पाते कि उन्हें जो सुविधा मिल रही है, वह किस योजना के अंतर्गत है। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्राम रथ इस अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सक्रिय और संवेदनशील है। यह दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जो दिखता है, वही अक्सर सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। प्रत्येक ग्राम रथ एक छोटा वाहन है जिस पर कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन लगी है। इसमें ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति है जिसका काम है कि कंप्यूटर में दी गई वीडियो क्लिप जगह-जगह चला कर लोगों को दिखाना। करीब 15 क्लिप मिलाकर कुल लगभग एक घंटे की है। सभी में बताने का प्रयास किया गया है कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम किये हैं। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस प्रचार पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन तंत्र के प्रमुख मुख्य सचिव स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सूचना और जनसंपर्क विभाग इन रथों का संचालन जिला परिषदों के माध्यम से कर रहा है। रथ के उद्धार के स्थानों पर स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन भी शामिल किये गए हैं। ग्राम रथों से ग्रामीण आबादी कितनी प्रभावित हो रही है इसका पता तो जब चुनाव होंगे उनके परिणाम ही देंगे मगर अभी ऊपर से सारा जोर इस बात पर है कि रथ के कार्यक्रमों में जो लोग आ रहे हैं उनकी विडियो रिपोर्टें सोशल मीडिया पर निरंतर डाली जाएं। सब जगहों से रथों के इवेंटों के फोटो और विडियो उलवाने के लिये जयपुर में बैठे प्रशासन के आला अफसर दिन रात नीचे के लोगों को हैरान-पेशान किये हुए हैं। यहां हमें उस मूल ढ़्द को समझना होगा जो आज की राजनीति में गहराई से मौजूद है-काम (सरकार का प्रदर्शन) बनाम धारणा (परिप्रेषण)। यह नये जमाने में लोकतंत्र का बदलता समीकरण है। लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप में यह माना जाता है कि मतदाता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर वोट देता है। लेकिन व्यवहार में स्थिति ऐसी होती नहीं है। मतदाता का निर्णय केवल ठोस उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक धारणाओं से भी उसका मन प्रभावित होता है जिसके आधार पर वह वोट देता है। आम आदमी का सरकारी तंत्र से पड़ने वाले रास्ते से भी उसकी सरकार के प्रति धारणा बनती है। लोग अक्सर अपनी धारणाओं के आधार पर वोट देते हैं। यह धारणा कई कारकों से बनती है जैसे मीडिया, सामाजिक संवाद, व्यक्तिगत अनुभव और राजनीतिक प्रचार। प्रचार रथ इस धारणा को नियंत्रित और दिशा देने का प्रयास करते हैं। वे एक कथा गढ़ते हैं कि सरकार विकासोन्मुख है, जनहितैषी है और लगातार काम कर रही है। यह कथा बार-बार दोहराई जाती है ताकि वह मतदाता के मन में स्थायी रूप से बैठ जाए। इसके साथ ही अब केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें भावनाओं की अपनी राजनीतिक पूंजी में अपने काम को भी बड़े पैमाने पर शामिल कर रही हैं ताकि संवैधानिक व्यवस्थाओं से बंधे शासन में भी उसकी वह पैट भी बने जो उसके भावनात्मक नेटवर्क के हिसाब से हो तथा मतदाता का चुनावी व्यवहार उसके पक्ष में प्रभावित हो। सरकार के विकास के कामों के प्रचार से सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास तो करती ही है, साथ ही वह विपक्ष के नेटवर्क का प्रत्युत्तर भी परोक्ष रूप से देती है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है। यदि विपक्ष यह धारणा बनाने में सफल हो जाता है कि सरकार निष्क्रिय है या विफल है, तो यह सत्तारूढ़ दल के लिए खतरा बन सकता है। प्रचार के ये रथ इस चुनौती का जवाब हैं। वे एक वैकल्पिक कथा प्रस्तुत करते हैं। मगर सरकारी कोष और मशीनों के जरिए चलाए जा रहे रथ अभियान पर यह सवाल उठाना स्वाभाविक ही है कि क्या यह लोकतांत्रिक आवश्यकता है या राजनीतिक प्रचार? यह प्रश्न इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू है। एक दृष्टिकोण से देखें तो जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलनी आवश्यक है। सरकार को अपने कार्यों का लेखा-जोखा देना चाहिए। संचार के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इस दृष्टि से शासन में बैठे लोगों को प्रचार रथ एक लोकतांत्रिक आवश्यकता प्रतीत होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब सरकारी संचारधर्मों का उपयोग सत्तारूढ़ दल की छवि सुधारने के लिए होता है, तो यह राजनीतिक प्रचार बन जाता है। इसमें उपलब्धियों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और कमियों को छिपाया जाता है।

ऐसे में निजी क्षेत्र में फल-फूल रहे प्रचार व्यवसाय को सरकार के इमेज मैनेजमेंट काम भरपूर मिल रहा है। प्रचार के रथ लोकतंत्र और राजनीति के बीच की उस धुंधली रेखा पर चलते हैं जहां जन-सूचना और राजनीतिक स्वार्थ एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। आज की राजनीति में सफलता का समीकरण बदल चुका है। अब केवल काम करना पर्याप्त नहीं है, और धारणा बनाना भी जरूरी है। इसके लिये भावी संचार आवश्यक हो गया है। राजनीतिक दलों ने यह समझ लिया है कि काम आधार है, धारणा प्रभाव है और संचार पुल है जो दोनों को जोड़ता है। ग्राम रथ इसी पुल का निर्माण करने में लगे हैं। वे उस जटिल वास्तविकता का हिस्सा हैं जहां सरकारें काम भी करती हैं और उसे दिखाने की आवश्यकता भी महसूस करती हैं। इसके लिये वे राजकोष का इस्तेमाल करने में परहेज नहीं करतीं। आज का मतदाता जागरूक भी है, लेकिन सोशल मीडिया के जाल में फंसा मतदाता धारणा से अंधेक प्रभावित होता है। इन्हीं परिस्थितियों में राजनीति सेवा और रणनीति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं और राजनेता अपने को जनता से सम्बद्ध रखने का प्रयास करते हैं। अंततः, लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि मतदाता कितनी सजगता से इन प्रचार माध्यमों को परखता है। यदि नागरिक केवल दिखावे से प्रभावित होंगे, तो राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन यदि वे वास्तविक काम और ठोस परिणामों को प्राथमिकता देंगे, तो प्रचार की सीमाएं स्वतः तय हो जाएंगी। इसलिए, असली प्रश्न यह है कि हम, मतदाता, उस प्रचार को कितनी समझदारी से ग्रहण करते हैं।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा

(वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक)

लोकतंत्र और पार्टी हाईकमान : निर्णय और निर्णायक



रामनिवास बैरवा

राजनीतिक पार्टियों के निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी ही अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं ढाल सकती, तब देश का लोकतांत्रिक आधार तो डांडाडोल होता ही है, उसकी भागीदार राजनीतिक पार्टियाँ भी, क्रमशः समाप्त होने की बाध्य होती हैं।

भारतीय जनता पार्टी का 'कांग्रेस मुक्त भारत' जैसा नारा या अभियान उसी ही बाध्यता का एक रूप है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तिलांजलि देकर 'हाई कमान' के चारों ओर अपने अनुयायियों को इकट्ठा करके राजनीति में सफल होने का खेल कर रहे होते हैं। यही 'हाई कमान' की निर्णायक भूमिका की परम्परा ही भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखायेगी।

जब ऐसी पार्टियों का आधार लोकतंत्र नहीं होकर 'पार्टी हाई कमान' ही निर्णायक बन जाते हैं तो सिद्धांतहीनता के अभाव में वे दूसरों पर लॉचन लगाते हैं, आपस में एक दूसरे का चरित्रहनन करते हैं। और फिर इस प्रकार से सभी पार्टियाँ गलीच बनकर रह जाती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को भी उसी गलीच चरित्रहनन के स्तर पर ले आती हैं, तब सब एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन जनता उन पार्टियों के द्वारा आपसी चरित्रहनन के साथ-साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी आदि को भी समय-समय पर अपना नारा बनाये रखने को बाध्य करती हैं। चूंकि

भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी पूंजीवादी लोकतंत्र के ऐसे आवश्यक विषय हैं, जिनको बनाये रखना उनके लिए आवश्यक है। उनको खतम करना उन कथित राजनीतिक पार्टियों के लिए घातक होता है, अतः कुछ और नया जोड़ने की कोशिश की जाती रही है।

जहां कांग्रेस गांधीजी की और स्वतंत्रता प्राप्ति को अपनी परम उपलब्धी होने का बखान करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रूढ़ियों को सनातन सत्य बताकर अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाये रखने का प्रयासरत रही है। लेकिन जिस संविधान आडू में राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता प्राप्त करती हैं, उसी संविधान को अपनी-अपनी सत्ता के स्थायित्व में अवरोध भी मानती है। अतः वे संविधान की व्याख्या अपने-अपने स्वार्थों के अनुसार करती हैं और नौकरशाहों का उपयोग करती हैं, विचारधारा को छोड़ देती हैं। इस प्रकार से लोगों की विचार भिन्नता को दबाये रखने के लिए एक ही व्यक्ति के आदेशों के अनुसार चलने की परम्परा डाली जाती है। पार्टी हाई कमान बनने का सबसे पहला प्रयोग 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। उस समय, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों के द्वारा कांग्रेस के मंच पर मोहम्मद अली जिन्ना को बेइज्जत करके मंच से ही नहीं कांग्रेस से भी हट जाने को मजबूर किया था। 'महात्मा' बनने के चक्कर में गांधीजी ने वह सब बाखुशी देखा और मौन रहकर कांग्रेस पार्टी की अलोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के 'हाई कमान' बने।

उसके बाद, जब तक गांधीजी जिंदा रहे, कांग्रेस के हाई कमान बने रहे और मंच के बाद राष्ट्रपिता बना दिये गये। लेकिन, 1920 में चरित्रहनन करने वालों को आगे की सम्भावनाएं कम दिखी, इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संस्था बनाकर आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 'कांग्रेस विहीन भारत' का नारा देकर, उसी 'हाई कमान' वाली व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक पार्टी के सहारे, बेशक सत्ता

भोग कर रही हो, लेकिन 'हाई कमान' के निर्णय लोकतंत्र को नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं।

संविधान का अध्याय-चार, 'राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांत' संविधान की आत्मा हैं और उनके लिए काम करना सभी सरकारों, सभी राजनीति पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। उनके लिए काम नहीं करना गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को निरन्तर बनाये रखना है, जिसका विपरीत परिणाम भ्रष्टाचार को अनिवार्यतः फलने-फूलने की परिस्थितियाँ निरन्तर बनाये रखना है। इस प्रकार उनके लिए, संविधान का अध्याय-चार, उनकी अपनी 'हाई कमान' प्रणाली के लिए कैसे रूकावट बना हुआ है, इसका ही उदाहरण देना काफी है।

गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को, जो कि उनका 'मूल-अधिकार' है, को आंशिक रूप से समाप्त करने के लिए, भारत की समाज व्यवस्था में अछूत-पिछड़ी जातियों को उक्त अध्याय में, संदर्भ देकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था लोगों के आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ ही जाति व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था के अनावश्यक बन जाने की अपेक्षा की गई थी। परन्तु, वही आरक्षण अब चुनावी लोकतंत्र की आवश्यकता के साथ-साथ 'हाई कमान' की प्रणाली के लिए भी अनिवार्य बन गया है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के संविधान के प्रावधान को अपना 'ट्रेडमार्क' मानती है, वहीं दूसरी अन्य पार्टियाँ विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण को अपनी 'हाई कमानका मास्टर स्ट्रोक' बनाने की कोशिशों में लगी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन व्यवस्था बनाये रखने को अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क बना चुकी है, उस पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण को सनातनी व्यवस्था यानि कि वर्ण-व्यवस्था या जाति-व्यवस्था को

समाज व्यवस्था का आवश्यक अंग अनाये रखने की आड़ में आरक्षण को खतम करने का स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है, उसी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का दाव खेले चुकी है। परंतु 2026 में अभी हुए 5 विधान सभाओं के आम चुनावों में किसी भी जनता पार्टी ने भी महिलाओं को उक्त 33 प्रतिशत की मात्रा में चुनावों में टिकित नहीं दिए।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किसी भी राजनीतिक पार्टी का हाई कमान करना चाहता है। क्योंकि कथित महिला आरक्षण पुरुष सत्ता को और मजबूती देने की ही प्रचारित किया गया है। आंकड़ों को देखें तो- अभी संसद में 80-85 महिला सांसद हैं, जो कि 543 सांसदों का 15.65 प्रतिशत है। जाहिर है कोई भी राजनीति पार्टी, महिला आरक्षण के द्वारा नारी मुक्ति को जोर-शोर से प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी, संसद में 15 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार रही है। लेकिन महिला आरक्षण के नाटक के पीछे इन 15.65 प्रतिशत महिलाओं की सीटें भी अपने पुरुष उम्मीदवारों को देने की कोशिश में संविधान को ही अपनी स्वायत्तता के लिए ढाल बना चुकी है। क्योंकि महिलाओं को नई बंधाई जाने वाली 33 प्रतिशत सीटों में समेटा जायेगा और वर्तमान 15.65 प्रतिशत सीटें अपने पुरुष उम्मीदवारों को दे देंगी। इसके अलावा एक और पक्ष यह है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का। और वह यह है कि वर्तमान में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने से उनकी नये-पुराने पुरुष उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी से हाथ धोना पड़ रहा है जो कि अपनी-अपनी पार्टियों में विद्रोह, पार्टियों के टूटने के साथ ही नई बनाकर नया हाई कमान का उभारना है जिससे जातियों पर उनकी पकड़ में फूट पड़ती है। इसीलिए 33 प्रतिशत संसद में सीटें

बढ़ाकर 'महिलाओं को आरक्षण' और उन्हें उसी सीमा में बांधकर रखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित संख्या तक ही सीमित रखा जा रहा है।

फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ रूख किया जाये।

राजीव गांधी की मौत के बाद, 1991 से कांग्रेस में कोई हाई कमान नहीं रही थी। तब तब के चुनाव आयुक्त टी. एन. शेणन ने कांग्रेस की फूट के बीच गांधी परिवार को फिर से हाई कमान की भूमिका में लाने के प्रयास में कथित चुनाव सुधार लागू किये, जिससे, अंततः सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हुआ और वह आज भी कांग्रेस की हाई कमान बनी हुई है। बेशक, राहुल गांधी को दूसरा हाई कमान बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन वह गांधी के सामने का जवाहर लाल नहीं है जो गांधी जी के बाद नया हाई कमान खड़ा कर सके। और यह राहुल गांधी की मानसिक सोच में नहीं है कि वह हाई कमान जैसे सर्व-सुविधाओं से संपन्न हैसियत को छोड़ दे। नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि कांग्रेस में राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत कम हो। क्यों कि वह राहुल गांधी के बहाने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जुट रख पा रहे हैं, अन्यथा जब कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होगा तो किससे लड़ा जायेगा। इसलिए, एक हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से।

हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से।

हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पोखरण परमाणु परीक्षण : 51 वर्ष बाद भी शौर्य, समस्याएं और विकास की अधूरी कहानी बयां करता परीक्षण स्थल

51 वर्ष बीत जाने के बाद भी खेतोलाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं



जुगल किशोर बिस्सा

पोकरण भारत की सामरिक शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा का गौरवशाली प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित इस छोटे से कस्बे ने वर्ष 1974 और 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों के कारण पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन राष्ट्रीय गौरव के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों को अनेक समस्याओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।

18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्मॉलिंग बुद्ध नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पांच परमाणु परीक्षण कर भारत को विश्व की परमाणु शक्तियों में शामिल कर दिया।

इन परीक्षणों के बाद पोकरण का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। देशभर में इसे राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा गया। वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सहित भारतीय वैज्ञानिकों की

भूमिका को सराहा गया। वर्ष 1998 के परीक्षणों ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई।

ग्रामीणों की समस्याएं और प्रभाव : परमाणु परीक्षण स्थल के सबसे निकट कई गांवों के लोगों का कहना है कि परीक्षणों के बाद क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ीं। ग्रामीणों में कैंसर, त्वचा रोग, आंखों में जलन, पशुधन पर प्रभाव तथा जन्मजात बीमारियों जैसी शिकायतें उठाई हैं। हालांकि इन दावों पर सरकार की ओर से कोई वैज्ञानिक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि परीक्षणों के समय धरती हिल गई थी और कई घरों में दरारें तक आ गई थीं। कई परिवारों का आरोप है कि वर्षों से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन कोई स्थायी मेडिकल रिसर्च या विशेष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बावजूद आज भी पोकरण में आसपास के गांवों में कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। खेतोलाई सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार का अभाव और खराब आधारभूत ढांचे की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि गांवों में पानी की सप्लाई कई-कई दिनों बाद होती है तथा ग्रामीणों को टैंकरो में पानी खरीदना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त रूप से संचालित नहीं हो पाते तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा

सुविधाओं का अभाव है। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं :- परमाणु परीक्षणों के बाद केंद्र सरकार तथा केंद्रस्थानों द्वारा कुछ विकास कार्य जुरू किया गया। क्षेत्र में सेना और रक्षा प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से सड़क और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई तथा परीक्षण क्षेत्र को प्रक्षुब्ध रखा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर पोकरण को देश की वैज्ञानिक उपलब्धि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े सीमित रोजगार अवसर भी क्षेत्र में बने। हालांकि स्थानीय लोग लंबे समय से विशेष पैसेज, कैंसर अस्पताल, बेहतर पेयजल योजना, पर्यटन विकास, शिक्षा संस्थान और युवाओं के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं।

मई महिने में ही परीक्षण क्यों किए गए? :- भारत सरकार द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण मई महिने में अलग-अलग समय पर किए जाने के पीछे कई सामरिक, वैज्ञानिक और मौसम संबंधी कारण माने जाते हैं। विशेषज्ञों और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह केवल संचार नहीं था, बल्कि रणनीतिक योजना का हिस्सा था।

रेगिस्तानी मौसम और साफ वातावरण :- पोकरण थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। मई महिने में यहां अत्यधिक गर्मी रहती है और आसमान सामान्यतः साफ रहता है। वैज्ञानिकों के लिए भूमिगत परीक्षण, उपकरणों की निगरानी और सैन्य गतिविधियों को

संचालित करना आसान माना गया। गर्म हवाओं और धूल भरे वातावरण के कारण विदेशी उपग्रहों की निगरानी से भी कुछ हद तक बचाव संभव माना जाता था।

विदेशी जासूसी उपग्रहों से बचाव : 1998 के परीक्षण अत्यंत गोपनीय तरीके से किए गए थे। उस समय अमेरिका सहित कई देशों के जासूसी उपग्रह भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। वैज्ञानिकों और सेना ने रात के समय काम किया तथा मई मौसम और रेतीले इलाके का फायदा उठाकर तैयारियां छिपाईं। माना जाता है कि मई की तेज गर्मी और धरती की ऊष्मा के कारण उपग्रहों को स्पष्ट गतिविधियां पकड़ने में कठिनाई हुई।

रणनीतिक और राजनीतिक समय :- 1974 के परीक्षण के समय भारत वैश्विक दबाव के बावजूद अपनी परमाणु क्षमता दिखाना चाहता था। वहीं 1998 में भारत ने खुद को खुलकर परमाणु शक्ति घोषित करने का निर्णय लिया। उस समय क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर चीन और पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां, एक बड़ा कारण थी।

भूमिगत परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थिति :- वैज्ञानिकों के अनुसार मई में जमीन की सूखी और कठोर स्थिति भूमिगत परीक्षणों के लिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी

दिवस मनाया जाता है।

क्या कोई धार्मिक या ज्योतिषीय कारण था? :- कुछ लोगों द्वारा समय-समय पर धार्मिक या ज्योतिषीय कारणों की चर्चा की जाती रही है, लेकिन सरकार या वैज्ञानिकों ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार परीक्षणों का समय मुख्य रूप से सुरक्षा, गोपनीयता, मौसम और सामरिक रणनीति को ध्यान में रखकर तय किया गया था।

आज भी कायम है गौरव और उपेक्षा का ढ़्द : -पोकरण आज भी भारत की सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहां हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस भूमि ने देश को परमाणु शक्ति बनाया, उसी क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

51 वर्ष बीत जाने के बाद भी खेतोलाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं। ग्रामीणों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें पोकरण को परमाणु नगरी के रूप में विशेष दर्जा देकर यहां आधुनिक अस्पताल, कैंसर उपचार केंद्र, उच्च शिक्षा संस्थान, पर्यटन विकास, पेयजल परियोजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध करवाएं, ताकि राष्ट्रीय गौरव के साथ स्थानीय जनता का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके।

-जुगल किशोर बिस्सा,
वरिष्ठ पत्रकार।

राशिफल

बुधवार 13 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन 1:30 तक, विष्णुभय योग रात्रि 8:35 तक, बालव कर्ण दिन 1:30 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-मेष, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग दिन 1:30 से रात्रि 12:18 तक है। आज अपरा एकादशी, भद्रकाली एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी (उड़ीसा), पंचक है। श्रेष्ठ चौघड़िया: लाघ-अमृत सूर्योदय से 9:04 तक, शुभ 10:43 से 12:23 तक, कर 3:42 से 5:22 तक, लाभ 5:24 से सूर्यास्त तक। राहकाल: 12:00 से 1:30 तक सूर्योदय 5:44, सूर्यास्त 7:02

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना पड़ सकता है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यवसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेंगी। व्यवसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यवसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यवसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटक हुए कार्य बने लगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बने लगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यवसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यवसायिक कार्यों के कारण पारदर्शी रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यवसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यवसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटक हुए कार्य बने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्यों में सुधार होगा। व्यवसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशावादन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बने लगे। व्यवसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक स्थानों